1	2	3	4
5	Tso Kar basin	J & K	Ladakh
6	Shallabugh Lake and marshes	J & K	Srinagar
7	Wular Lake	J & K	Baramulla
8	Hygam Lakh	J & K	Baramulla
9	Mirgund Lake	J & K	Badgam
10	Hokersar	J & K	Srinagar Badgam
11	Pong Dam Lake	H. P.	Kangra
12	Harike Lake	Punjab	Amritsar
13	Dihaila Jheel	M. P.	Shivpuri
14	Keoladeo Ghana National Park	Rajasthan	Bharatpur
15	Sultanpur Jheels	Haryana	Gurgaon
16	Sambhar, Phulera and Didwana Salt Lakes	Rajasthan	
17	Great Rann of Kutch	Gujarat	Kutch
18	Little Rann of Kutch	Gujarat	Kutch
19	Nalsarovar Lake and the Surendranagar Reservoirs	Gujarat	Ahmedabad and Surendranagar
20	Chaurs of North Bihar and West Bengal	Bihar	
21	Khabartal	Bihar	Begsarai
22	Wetlands in Manas Wildlife Sancturay	Assam	Barpeta and Koharajhar
23	Dipat Beel	Assam	Kamrup
24	Wetlands in Kaziranga N.P.	Assam	Nowgong and Sibsagar
25	Keibul Lamjao N.P.	Manipur	Imphal
26	Loktak Lake	Manipur	Imphal
27	Chilka Lake	Orissa	Ganjam & Puri
28	Kolleru Lake	A. P.	Krishna & West Godavari
27	Pulicat Lake	A. P.	Nellore
30	Kaliveli Tank & Yedayanthittu Estuary	T. N.	South Arcot
31	Point Calimere and Vedaranejam Salt Swamp	T. N.	Thanjavur
32	National Chambal (Gharial) Wildlife Sanctuary	U. P. Rajasthan M. P.	Agra Kota Morena

प्रदूषण अवरोधक संयंत्र

846. **श्री शिवप्रसाद धनपुरिया** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने 10 दिसम्बर, 1991 के अपने नोटिस के द्वारा गंगा तट पर स्थित 1500 औद्योगिक इकाइयों को निदेश दिया था कि वे 31 दिसम्बर, 1991 तक प्रदूषण नियंत्रण मानदण्डों के

अनुसार प्रदूषण अवरोधक संयंत्र लगा लें, जिसके न करने पर इन इकाइयों को बन्द कर दिया जायेगा ;

(ख) उच्चतम न्यायालय के निदेश का पालन कितनी इकाइयों ने किया है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि पर्यावरण और वन विभाग ने दिनांक 12 फरवरी, 1992 की अपनी अधिसूचना द्वारा प्रदूषण फैलाने वाली उपरोक्त औद्योगिक इकाइयों को ऐसे संयंत्र लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि से एक दो वर्षों तक की अवधि और प्रदान की थी, यदि हां, तो ऐसी इकाइयों के नाम क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) और (ख) सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिनांक 10 दिसम्बर, 1991 के निर्णय द्वारा आदेश दिया है कि गंगा नदी के तट पर स्थित सभी उद्योग पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा प्रदूषण निवारण उपकरण लगाने संबंधी अनुदेश का अनुपालन करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में 15 जनवरी, 1992 तक शपथ पत्र दायर कर दें। आगे यह भी उल्लेख किया गया था कि जो उद्योग प्रदूषण निवारण के लिए आवश्यक कदम नहीं उठा सके हैं उन्हें बन्द करने के आदेश दिए जाएं। किन्तु ज्यादातर इकाइयों द्वारा इन निदेशों का निश्चित तिथि तक अनुपालन नहीं कर पाने के कारण उच्चतम न्यायालय ने इन इकाइयों द्वारा शपथ पत्र जमा कराने की समय सीम को बढ़ा दिया था।

(ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 12 फरवरी, 1992 को एक अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा 15 मई, 1981 से 31 दिसम्बर, 1993 के दौरान प्रारंभ किए गए उद्योगों द्वारा बहिःस्राव उपचार संयंत्र पूरा करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई समय सीमा की अवधि को 30-11-92 तक बढ़ा दिया था। 16 मई, 1981 से पूर्व जिन उद्योगों ने अपना उत्पादन शुरु कर दिया था उनके लिए समय-सीमा 31 दिसम्बर, 1992 तक इस शर्त के साथ दी जाएगी कि वे संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संतुष्ट करते हुए समयबद्ध तरीके से बहिःस्राव उपचार सुविधाओं पर वास्तविक कार्य शुरू करने के लिए ठोस कदम उठाएगे। उपरोक्त अधिसूचना उन उद्योगों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने वास्तविक कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किया है और चरणबद्ध रूप से बहिः स्राव उपचार संयंत्र के लिए ठोस प्रमाण नहीं दिखाए है। उपरोक्त अधिसूचना सामान्य प्रकृति की और अधिकार प्रदान करने वाली है न तो यह विशिष्ट उद्योग या क्षेत्र से संबंधित है और न ही किसी उद्योग को अपने आप से विस्तार प्रदान करती है।

मध्य प्रदेश में बंजर पहाड़ एवं पठार

847. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में वृक्षविहीन पहाड़ एवं पठार कितने क्षेत्र में फैले हैं, और

(ख) क्या इन पहाड़ों एवं पठारों पर वनरोपण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है और क्या ऐसी योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) मध्य प्रदेश में पर्वतों और पठारों को मिलाकर दर्ज किया गया वन क्षेत्र 155414 वर्ग किलोमीटर है।

(ख) मध्य प्रदेश में राज्य और केन्द्र सरकार की विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत वनीकरण किया जाता है। जहां तक राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड का संबंध है, मध्य प्रदेश